पीएमजीएसवाई की तर्ज पर यूपी में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना

लोक निर्माण विभाग के बजट में 2455 करोड़ रुपये की बढ़ोत्तरी

चार नए एक्सप्रेसवे बनने से और बेहतर होगी प्रदेश में कनेक्टिविटी

बुनियादी सुविधाएं बढ़ाने के लिए योगी सरकार ने खोला खजाना

2700 करोड़ से ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कें बनेंगी

अमर उजाला ब्यूरो

लखनऊ। योगी सरकार ने आगामी वित्त वर्ष के बजट में बुनियादी सुविधाओं के लिए खजाना खोल दिया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) की तर्ज पर मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना (सीएमजीएसवाई) प्रारंभ की गई है। लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) को वर्ष 2024-25 के मुकाबले 2455 करोड़ रुपये अधिक दिए गए हैं। वहीं, 4 नए एक्सप्रेसवे के बनने से प्रदेश में कनेक्टिवटी बेहतर होगी।

पीडब्ल्यूडी के लिए वित्त वर्ष 2024-25 में 34401 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया था, जो आगामी वित्त वर्ष के बजट में बढ़ाकर 36855.90 करोड़ रुपये दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ग्राम योजना के अंतर्गत नवनिर्माण, पुनर्निर्माण व मिसिंग लिंक के लिए नई योजना प्रारंभ की गई है। इस योजना के लिए 200 करोड़ रुपये का बजट व्यवस्था की गई है।

पुलों, ओवरब्रिजों और अंडरपास के लिए 1450 करोड़, स्टेट हाईवे के लिए 2900 करोड़, राज्य सड़क निधि में रखरखाव के लिए 3000 करोड़ और नए निर्माण के लिए 2800 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में मार्गों के लिए 2700 करोड़ और पुलों के लिए 1600 करोड़ रुपये अलग से दिए गए हैं।

1200 करोड़ रुपये शहरी क्षेत्रों में बाईपास, रिंगरोड और फ्लाईओवर के लिए

350 किमी लंबा होगा विंध्य एक्सप्रेसवे

चार नए एक्सप्रेसवे के लिए 1050 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान

आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे और गंगा एक्सप्रेसवे को जोड़ने के लिए प्रवेश नियंत्रित ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण होगा। आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे से गंगा एक्सप्रेसवे कौसिया (हरदोई) वाया फर्रुखाबाद तक प्रवेश नियंत्रित ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण कराया जाएगा, जिसके लिए 900 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है। इस परियोजना की कुल लागत 7 हजार करोड़ रुपये होगी।

- इसके अलावा गंगा एक्सप्रेसवे को प्रयागराज, मिर्जापुर, वाराणसी, चंदौली होते हुए सोनभद्र से जोड़ने के लिए विंध्य एक्सप्रेसवे का निर्माण होगा, जिसकी लंबाई 350 किमी होगी। इसके लिए बजट में शुरुआती 50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। वहीं मेरठ को हरिद्वार से जोड़ने के लिए गंगा एक्सप्रेसवे विस्तारीकरण एक्सप्रेसवे का निर्माण प्रस्तावित है, जिसके लिए 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। बुंदेलखंड-रीवा एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए भी 50 करोड़ रुपये दिए गए हैं।

461 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के साथ डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के लिए लगभग साढ़े नौ हजार करोड़ रुपये का निवेश अनुमानित हैं।

1000 करोड़ रुपये जेवर एयरपोर्ट से गंगा एक्सप्रेसवे वाया बुलंदशहर संपर्क एक्सप्रेसवे तक प्रवेश नियंत्रित ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे के लिए

800 करोड़ रुपये औद्योगिक व लॉजिस्टिक पार्क तक मार्गों के लिए

सड़क सुरक्षा के लिहाज से दुर्घटना बहुल क्षेत्रों के सुधार, रोड सेफ्टी कार्यों और सुंदरीकरण के लिए 250 करोड़ रुपये।

पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर ई-वे हब की स्थापना के लिए 144 करोड़।

आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे के सुदृढ़ीकरण के लिए 800 करोड़।